औपनिवेशिक भारत में अकाल (1770 ई0– 1880 ई0): एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डा0 अवधेश कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर –इतिहास
डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय,
सन्त रविदास नगर, भदोही

सारांश

भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना के पश्चात औपनिवेशिक शासन का प्रभाव सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रों पर परिलक्षित हुआ। प्राचीन काल से ही भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित रही है यद्यपि कि समय समय पर सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास किया गया फिर भी भारत का अधिकांश क्षेत्र सिंचाई के साधनों से आच्छादित न हो सका। 1770 ई० में निचले बंगाल तथा बिहार में पड़ने वाला अकाल बहुत भयानक था तथा आधिकारिक आकलनों के अनुसार उस समय की जनसंख्या का एक तिहाई भाग लगभग 1 करोड़ लोग अकाल के कारण मर गए । 19वी शताब्दी के अंत तक भारत में 20 से अधिक अकाल पड़े। इन अकालों में पश्चिमोत्तर प्रांत में पड़ने वाला 1861 ई० का अकाल अत्यंत महत्वपूर्ण है जोकि वर्षा की कमी के कारण पड़ा। इस अकाल से 25000 वर्ग मील का क्षेत्रफल तथा 13 मिलियन लोग प्रभावित हुए। उड़ीसा के अकाल को भारतीय अकालों के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी के फलस्वरूप सर जार्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में जाँच आयोग का गठन किया गया जिसने अकाल सहायता नीतियों को निर्धारित करने हेतु आधारशिला प्रदान की। 1888 ई० के भारतीय अकाल आयोग की रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया कि सरकार को अपने संसाधनों के माध्यम से अकाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत सहायता पहुंचाना चाहिए साथ ही इस आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि अकाल संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए जिसे स्थानीय सरकार के द्वारा लागू किया जाए तथा इस कार्य हेतु आर्थिक नियंत्रण भारत सरकार का होगा।

मुख्य शब्द – औपनिवेशिक, कृषि ,वर्षा ,खाद्यान्न, राहत सहायता, व्यापार, फसल

भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना के पश्चात औपनिवेशिक शासन का प्रभाव सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रों पर परिलक्षित हुआ। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव के सन्दर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव कहीं अधिक प्रभावी रूप में हष्टिगोचर हुये। औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना था क्यों कि भारत में भू राजस्व की वसूली करके अपने औपनिवेशिक हितों को संरक्षित किया जा सकता था। प्राचीन काल से उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र उपजाऊ होने के कारण शासक वर्ग के लिए भू–राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है।

19 वीं शताब्दी के प्रारंभ होने तक इन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो चुका था तथा अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी के द्वारा इन क्षेत्रों में नई भू राजस्व प्रणाली जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, संयुक्त प्रांत के क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में गेंहू, चावल, मटर, कपास, अरहर, मूंग, खेसरी, तिल, मक्का, कोदो, चना, ज्वार, बाजरा आदि फसलों का उत्पादन होता था[1]। इन सबके अतिरिक्त तंबाकू तथा अफीम की भी खेती की जाती थी। इन क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई, नदियों, नहरों, तथा तालाबों, आदि के द्वारा की जाती थी। इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने तथा उर्वर भूमि क्षेत्र होने के बावजूद औपनिवेशिक शासन के अधीन अकाल के दुष्परिणाम परिलक्षित होने के कारणों की विवेचना अधिक प्रासंगिक हो जाती है।

अकाल का तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति से है, जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या खाद्यान्न की उपलब्धता न होने के कारण अत्यधिक भूख की स्थिति का सामना करती है[2]। किन्तु अकाल की यह परिभाषा प्राचीन और मध्यकालीन आर्थिक जीवन की दृष्टि से उचित प्रतीत होती है क्योंकि यातायात के साधनों की कमी तथा पूर्णरूप से व्यापार विकसित न होने के कारण मनुष्य को अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर होना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में फसलों का उत्पादन न होने के कारण लोगों को देश के अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध खाद्यान्न का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था। ऐसी अकाल की स्थिति में खाद्यान्न की कमी के कारण अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती थी। आधुनिक काल में उद्योगों, व्यापार तथा यातायात के साधनों में नवीन परिवर्तनों के कारण अकाल के अर्थों तथा उसकी प्रकृति में काफी परिवर्तन आया[3]। नई परिस्थितियों में खाद्यान्नों की कमी के स्थान पर खाद्यान्नों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण वह गरीबों की पहुँच से बाहर हो गए और इसलिए गरीबों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। 1880 ई० की भारतीय अकाल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग मील तथा ब्रिटिश भारत की जनसंख्या 24 करोड़ थी[4]। इसमे से लगभग 6 लाख वर्ग मील का क्षेत्रफल देशी रियासतों (जोकि ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थी) के अधीन था जिसमे 5 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी जबकि शेष 9 लाख वर्ग मील के ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र में 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी।

राज्यवार क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का विवरण निम्नवत है[5]–

ब्रिटिश प्रांत	वर्गमील क्षेत्रफल	लाख में जनसंख्या
बंगाल, असम के साथ	200,000	65
मद्रास	140,000	$31\frac{1}{2}$
बॉम्बे	77,000	$14\frac{1}{4}$
सिंध	47,000	2
उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध	105,000	42
पंजाब	105,000	$17\frac{1}{2}$
मध्य प्रांत	85,000	$8\frac{1}{4}$
बर्मा	90,000	$2\frac{3}{4}$
अजमेर और कुर्ग	4,000	$\frac{1}{2}$
	853,000	$183\frac{3}{4}$

ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रशासित देशीय राज्य	वर्ग मील क्षेत्रफल	लाख में जनसंख्या
मैसूर	29,000	5
बरार	18,000	$2\frac{1}{4}$
	47,000	$7\frac{1}{4}$
पूर्ण कुल	900,000	191

	वर्गमील क्षेत्रफल	लाख मेंजनसंख्या
राजपूताना के राज्य	131,000	10
मध्य भारत एवं बुंदेलखंड	89,000	$8\frac{1}{4}$
हैदराबाद(निजाम)	80,000	9
बड़ौदा	4,000	2
बंगाल में देशीय राज्य (मुख्यतः पहाड़ी)	46,000	$2\frac{1}{2}$
मद्रास	10,000	$3\frac{1}{2}$
बॉम्ब	66,000	$6\frac{3}{4}$
उत्तर पश्चिम प्रांत	5,000	$\frac{1}{2}$
पंजाब	115,000	$5\frac{1}{2}$
मध्य प्रांत	29,000	1
कुल	575,000	49

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्रांतियों से पूर्व यूरोप में भी अकाल एक प्राकृतिक विपदा के रूप में पड़ता था तथा विश्व का कोई भी हिस्सा अकाल पड़ने से मुक्त नहीं था[6]। प्राचीनकाल से ही भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित रही है यद्यपि कि समय समय पर सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास किया गया फिर भी भारत का अधिकांश क्षेत्र सिंचाई के साधनों से आच्छादित न हो सका। भारत में अकाल पड़ने के मुख्य कारण वर्षा की कमी, सूखा, बाढ़, फसलों का बीमारियों से ग्रसित होना तथा टिड्डी दलों का आक्रमण[7] होता था। इन कारणों के अतिरिक्त अत्यधिक कराधान तथा अनुपयुक्त भूमि राजस्व नीतियों तथा शासक वर्ग के द्वारा अकालों से निपटने में तत्परता तथा सहानुभूति की कमी भी अकालों के दुष्प्रभावों को बढ़ा देते थे।

औपनिवेशिक शासन के अधीन भारत में किसी न किसी क्षेत्र में अकाल पड़ते रहे किन्तु जैसा कि भारतीय अकाल आयोग के 1901 रिपोर्ट में उल्लिखित है, औपनिवेशिक शासन के द्वारा अकाल की समस्या से निपटने के लिए अथवा अकाल के दौरान पीड़ितों की सहायता के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। जब भी अकाल पड़ते थे बहुत छोटे स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया जाता था जो कि अपर्याप्त होता था[8]।

1770 ई० में निचले बंगाल तथा बिहार में पड़ने वाला अकाल बहुत भयानक था तथा आधिकारिक आकलनों के अनुसार उस समय की जनसंख्या का एक तिहाई भाग लगभग एक करोड़ लोग अकाल के कारण मर गए[9]। 1784 ई० में भारत के ऊपरी हिस्सों में पड़ने वाले अकाल का क्षेत्रफल 1770 ई० में पड़ने वाले अकाल के क्षेत्र से कहीं अधिक था तथा इस के प्रभाव कही अधिक भयानक थे। 1781 ई० व 1782 ई० में ईस्ट इंडिया कंपनी व हैदर अली के बीच हुए युद्धों तथा सूखे के कारण मद्रास में अकाल पड़ा[10]। 1781 ई० में मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी जिलों व हैदराबाद और बंबई प्रेसिडेंसी के दक्षिणी जिलों में अकाल पड़ा। 1792 ई० में अकाल के दुष्प्रभाव और दिखाई पड़े लेकिन इस वर्ष मद्रास सरकार की ओर से राहत कार्य करके अकाल प्रभावित लोगों तक सहायता पहुचाने का प्रयास किया गया। 1802 ई०में वर्षा की कमी से बंबई प्रेसिडेंसी, हैदराबाद तथा मद्रास के उत्तरी जिलों में अकाल पड़ा और उसी वर्ष वर्षा के अभाव में पश्चिमोत्तर प्रांत में बहुत भयानक अकाल पड़ा जोकि लगभग 1804 ई०तक चलता रहा।

1806 ई०में पुनः वर्षा के अभाव में मद्रास प्रेसिडेंसी तथा दक्कन के जिलों में अकाल पड़ा। उस समय दान देने वाले संगठनों से दान प्राप्त करने की प्रत्याशा में बहुत बड़ी भीड़ मद्रास आने लगी जिससे यह विचार विमर्श प्रारंभ हुआ कि लोगों को उनके घरों के नजदीक रोजगार प्रदान किया जाए तथा सरकार खाद्यान्न का आयात करके आंतरिक क्षेत्रों तक उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करे[11]। 1812–13 ई० में गुजरात तथा उसके निकट स्थ क्षेत्रों में पड़ने वाले सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए मद्रास सरकार द्वारा घोषित व्यापार में अहस्तक्षेप नीति का अनुसरण बंबई सरकार द्वारा किया गया तथा सरकार ने आयात–निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। इस अकाल का प्रभाव राजपूताना तथा पश्चिमोत्तर प्रांत के कुछ जिलों तक फैला हुआ था। 1824–25 ई० में भी बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी हिस्सों में अकाल पड़ा यद्यपि यह अकाल बहुत भयानक नही था। मिस्टर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन बंबई के तत्कालीन गवर्नर यद्यपि कि प्रारंभ में खाद्यान्नों के आयात को प्रोत्साहन देना चाहते थे अथवा आयातकर्ताओं को न्यूनतम लाभ की गारंटी देना चाहते थे किन्तु कुछ विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने यह पाया कि अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होगा[12]।

1833 ई० में पुनः मद्रास प्रेसिडेंसी में भयानक अकाल पड़ा किन्तु आश्चर्यजनक रूप से सरकार ने इस आपदा को समय रहते पहचाना तथा राहत सहायता पहुंचाई फिर भी गुन्टूर जिले में जिसकी जनसंख्या 5 लाख थी वहाँ पर भुखमरी से 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी । 1837 ई० में वर्षा की कमी के फलस्वरूप गङ्गा यमुना के दोआब इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली में गंभीर अकाल पड़ा किन्तु सरकार के द्वारा राहत सहायता न किए जाने के कारण अत्यधिक संख्या में लोगों की मौत हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता हस्तांतरित होकर क्राउन के अधीन आने के पश्चात तथा 19वी शताब्दी के अंत तक भारत में बीस से अधिक अकाल पड़े। इन अकालों में पश्चिमोत्तर प्रांत में पड़ने वाला 1861 ई० का अकाल अत्यंत महत्वपूर्ण है जोकि वर्षा की कमी के कारण पड़ा। इस अकाल से 25000 वर्ग मील का क्षेत्रफल तथा 13 मिलियन लोग प्रभावित हुए[13]। सरकार ने निःशुल्क राहत प्रदान करने का प्रयास किया तथा दान दाताओं के द्वारा भी ऐसे लोगों को सहायता प्रदान की गयी। इस आपदा के पश्चात सरकार के द्वारा कर्नलबेयर्ड स्मिथ के नेतृत्व अकाल आयोग का गठन किया[14]।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से बंगाल तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया।ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासको का यह मानना था कि जहां एक ओर कंपनी को एक निश्चित आय प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर किसानों व जमींदारो में भी समृद्धि आएगी तथा उन्हें खुशहाली प्राप्त होगी किन्तु कुछ समय पश्चात ही औपनिवेशिक शासन की इस नई भू राजस्व प्रणाली के दुष्परिणाम सामने आने लगे। 1860 ई० के पश्चिमोत्तर प्रांत में अकाल के पश्चात लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नियुक्त किए गए बेयर्डस्मिथ ने अपने रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि अकाल खाद्यान्न की कमी के कारण नहीं पड़े अपितु इनका मूल कारण भूखे लोगों तक खाद्यान्न का न पहुँच पाना था । उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि अकालों का

दुष्प्रभाव लोगों के दिन प्रति दिन के जीवन तथा समृद्धि के प्रति उनके विकास अथवा अवनति पर निर्भर करती है बजाय अन्य सुविधाये जैसे नहर अथवा सड़क की सुविधा। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि सूखा अथवा अन्य नकारात्मक प्रभावों से लोगों की लड़ने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जिसके अंतर्गत वह रह रहे है तथा विकसित हो रहे है, को कितनी पूर्णता के साथ लागू किया गया है[15]।

1866–67 ई० में पड़ने वाला उड़ीसा के अकाल का प्रभाव बहुत भयान कथा इसमें न केवल उड़ीसा को बल्कि कलकत्ता से मद्रास तक पूर्वी तटों के विभिन्न क्षेत्रो ंको भावित किया। उड़ीसा के अकाल को भारतीय अकालों के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी के फलस्वरूप सर जार्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में जाँच आयोग का गठन किया गया[16] जिसने अकाल सहायता नीतियों को निर्धारित करने हेतु आधार शिला प्रदान की। इस आयोग को अकाल के कारणों तथा इस समस्या से निपटने के लिए समायान्तर्गत उपाय किए जाने, अगर नहीं तो उनके ना होने के कोई वैध कारण होने और क्या भविष्य में इस प्रकार की घटनाओ को रोका या कम किया जा सकता है, के संबंध में जाँच हेतु कहा गया था[17]।

स्र जार्ज कैंप बेल ने इस अकाल के संबंध में उल्लेख किया कि चारों तरफ पड़े हुए मनुष्यों के अवशेषों को देखकर वह दंग रह गए, भारतीय दृष्टिकोण से अकाल का क्षेत्रफल कम था तथा यह कुछ लाख लोगों तक सीमित था एवं इसके तीव्रता की अवधि भी बहुत कम थी, यह आधे वर्ष से भी कम की अवधि का था किन्तु इन सीमाओ के बावजूद यह 19 वीं शताब्दी में भारत के किसी अन्य भाग में पड़ने वाले अकालों में सब सेतीव्र अकाल था[18]। उड़ीसा के अकाल का मुख्य कारण वर्षा का न होना और जिसके फलस्वरूप शरद कालीन फसलों का न होने के साथ ही बाहर से खाद्यान्न के आयात का लगभग पूर्णतः अभाव होना था[19]। अकाल के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। जार्ज कैंपबेल के आयोग ने यह पाया कि समायान्तर्गत पर्याप्त उपाय नहीं किए गए और इसके लिए तत्कालीन बंगाल के सर्वोच्च अधिकारी जिम्मेदार थे। बंगाल की सरकार ने परिस्थितियों का सही आकलन नहीं किया तथा केन्द्रीय सरकार को गुमराह किया[20]। यद्यपि कि कुछ स्थानीय अधिकारियों ने अकाल के प्रारम्भिक दौर में समस्या के संबंध में चेतावनी दी थी किन्तु उन्हें अनसुना कर दिया गया और 1866 ई० के बसंत तक ही समस्या को उचित प्रकार से समझ जा सका। अप्रैल 1866 ई०में कटक के मजिस्ट्रेट ने यह रिपोर्ट दी कि अकाल की गंभीर समस्या का कोई आधार नहीं है। जब कि कुछ दिन बाद मई में उन्हे तथा उनके सहयोगियों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसकी तुलना उस जहाज से की जिसमें अचानक यह पता चला की सारा सामान खत्म हो गया है[21]।

भारतीय अकाल आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अकाल केवल प्राकृतिक कारणों का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे अनेक प्रशासनिक, आर्थिक तथा अन्य कारण भी विद्यमान थे। आयोग ने यह स्वीकार किया कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, वर्षा पर आधारित खेती, अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति ने अकाल की तीव्रता को बढाया। साथ ही राजस्व नीति की कठोरता और किसानों की सीमित क्रय शक्ति ने ग्रामीण समाज को संकट के समय अधिक असुरक्षित बना दिया। रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित किया गया कि परिवहन, संचार तथा बाजार व्यवस्था के विकास के बावजूद अकाल राहत व्यवस्थाएँ कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रभावी नहीं थीं। इस कारण सरकार ने भविष्य में अकाल की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए सिंचाई विस्तार, राहत कोष की स्थापना, तथा अकाल संहिता जैसे उपायों को आवश्यक माना।

संदर्भ

1. दत्त, रोमेश, *भारत का आर्थिक इतिहास,* खंड–1,नई दिल्ली, पुनःसंस्करण, 2006, पृष्ठ–152–160 ।

2. साउथ हार्ड, *फेमिन,* इन साई क्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, खंड–अप, पृष्ठ–85, भाटिया, बी० एम०, *फेमिनइन इंडिया,* दिल्ली, 1967, पृष्ठ–1 में उद्धृत ।

3. भाटिया, बी० एम०, *पूर्वोक्त* ।

4. *इंडियन फेमिन कमीशन रिपोर्ट,* भाग–1, लंदन,1880, पृष्ठ–3 ।

5. *वही* ।

6. देखे, वलफोर्ड, *फेमिन ऑफ द वर्ल्ड* ,पास्ट एंडप्रेजेंट, जर्नल ऑफ स्टेटिस्कल सोसाइटी, खंड–•सप (1878), पृष्ठ–433–526, पूर्वोक्त, भाटिया, बी० एम० , पृष्ठ–1

7. मजूमदार, आर०सी०, *हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल,* खंड–५, ब्रिटिश पैरामौंटेसी एंड इंडियन रेनेसा, पार्ट–1 , मुंबई, 2002, पृष्ठ–828 ।

8. *वही* ।

9. *इंडियन फेमिन कमीशन रिपोर्ट,* भाग–1, लंदन,1880, पृष्ठ–9।

10. *वही* ।

11. *वही,* पृष्ठ–10 ।

12. *वही* ।

13. *वही,* पृष्ठ–829 ।

14. *वही* ।

15. बेयर्ड स्मिथ की रिपोर्ट, 14 अगस्त 1861, पैरा–36, आर०सी०,दत्त, *उपरोक्त,* खंड–२, पृष्ठ–273–274।

16. मजूमदार, आर०सी०, *पूर्वोक्त,* पृष्ठ–829।

17. सरजार्ज, कैंपबेल, *मेमोयर्स ऑफ इंडियन्स कैरियर,* पृष्ठ–149, आर०सी०, मजूमदार, *पूर्वोक्त,* पृष्ठ–829 में उद्धृत।

18. *वही* ।

19. *वही* ।

20. *वही* ।

21. *वही* ।